IDEAL INSTITUTE

CURRENT AFFAIRS BOOSTER

28 – 05 - 2022

SATURDAY

SSC | BANK | RRB

NDA | CDS | AIR-FORCE

UPP | UP-SI | UPSSSC

IDEAL INSTITUTE

IAS/PCS/SSC/BANK/RAILWAY

ADD.- Crossing No.9, Sharda Nagar, Kakadev, Kanpur

9335615537, 7499333337

1. भारतीय उपन्यास 'टॉम्ब ऑफ सैंड' ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री (Geetanjali Shree) और अमेरिकी अनुवादक डेज़ी रॉकवेल (Daisy Rockwell) ने "टॉम्ब ऑफ सैंड" के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। मूल रूप से हिंदी में लिखी गई, यह हाई-प्रोफाइल पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है, जो दुनिया भर के उन उपन्यासों को मान्यता देती है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। 50,000 पाउंड ($63,000) की पुरस्कार राशि को नई दिल्ली की श्री और रॉकवेल के बीच विभाजित किया जाएगा, जो वरमोंट में रहते हैं।

"टॉम्ब ऑफ सैंड" ब्रिटेन में एक छोटे प्रकाशक टिल्टेड एक्सिस प्रेस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसकी स्थापना अनुवादक डेबोरा स्मिथ ने की थी, जिन्होंने एशिया से किताबें प्रकाशित करने के लिए हान कांग की "द वेजिटेरियन" का अनुवाद करने के लिए 2016 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर जीता था।

पुस्तक का सार:

किताब एक अस्सी साल की विधवा की कहानी कहती है जो भारत और पाकिस्तान में उपमहाद्वीप के 1947 के उथल-पुथल वाले विभाजन के दौरान परंपरा को त्यागने और अपने अनुभवों के भूतों का सामना करने का साहस करती है। श्री की किताब ने लंदन में एक समारोह में पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए पोलिश नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता ओल्गा टोकारज़ुक, अर्जेंटीना के क्लाउडिया पिनेइरो और दक्षिण कोरियाई लेखक बोरा चुंग सहित पांच अन्य फाइनलिस्ट को हराया।

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में:

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हर साल यूके या आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास के अनुवादित काम के लिए दिया जाता है। यह अंग्रेजी भाषा के कथा साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार के साथ चलाया जाता है। पुरस्कार की स्थापना अन्य भाषाओं में कथा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जो ब्रिटेन में प्रकाशित पुस्तकों का केवल एक छोटा हिस्सा है और साहित्यिक अनुवादकों के अक्सर अनजाने काम को सलाम करने के लिए है।

2. एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने इंडोनेशिया को 16-0 से हराया

भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप 2022 के रोमांचक पूल ए गेम में इंडोनेशिया पर 16-0 से जीत दर्ज करते हुए अंतिम क्वार्टर में छह गोल दागकर एशिया कप के सुपर 4 चरण के लिए क्वालीफाई किया। भारत एशिया कप के सुपर 4 दौर में जापान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया के साथ शामिल हुआ। भारत को क्वालीफाई करने के लिए कम से कम 15-0 के अंतर से प्रतियोगिता जीतने की जरूरत थी और युवा पक्ष ने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया ।

भारत और पाकिस्तान दोनों पूल ए में जापान के पीछे चार-चार अंक पर समाप्त हुए, लेकिन धारकों ने बेहतर गोल अंतर (1) के आधार पर सुपर 4 के लिए क्वालीफाई किया। पाकिस्तान को इससे पहले दिन में जापान से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा था। एशिया कप के चल रहे संस्करण में यह भारत की पहली जीत थी क्योंकि उन्हें पूल ए में पहले स्थान पर रहने वाले जापान के हाथों 2-5 से हार का सामना करने से पहले पाकिस्तान द्वारा 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया गया था। पूल में खेले गए तीनों मैचों में जापान ने जीत हासिल की।

3. 26 साल की अभिलाषा बराक बनीं भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर

अभिलाषा बराक

हरियाणा की कैप्टन अभिलाषा बराक (Abhilasha Barak) अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एक लड़ाकू विमानवाहक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। नासिक में आर्मी एविएशन के डीजी और कर्नल कमांडेंट द्वारा उन्हें 36 अन्य सेना पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया। उन्हें 2072 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की दूसरी उड़ान के लिए सौंपा गया है। उन्हें 2018 में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से भारतीय सेना में शामिल किया गया था।

कैप्टन अभिलाषा बराक का करियर:

•कैप्टन बराक द लॉरेंस स्कूल, सनावर की पूर्व छात्रा हैं। उन्होंने 2016 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बी-टेक के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उन्हें डेलॉइट, यूएसए से नौकरी का ऑफर आया था।

•सेना वायु रक्षा कोर के साथ उनके लगाव के दौरान, उन्हें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा सेना वायु रक्षा के लिए रंगों की प्रस्तुति के लिए एक आकस्मिक कमांडर के रूप में चुना गया था।

•उन्होंने आर्मी एयर डिफेंस यंग ऑफिसर्स कोर्स में 'ए' ग्रेडिंग हासिल की, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और एयर लॉज कोर्स में 75.70 प्रतिशत और प्रमोशनल परीक्षा, पार्ट बी, अपने पहले प्रयास में पास की।

4. प्रधानमंत्री मोदी ने 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा एजेंसियों से अमृत सरोवर के तहत बनने वाले जल निकायों के साथ अपनी परियोजनाओं का नक्शा बनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह एक जीत की स्थिति होगी क्योंकि अमृत सरोवर के लिए आवश्यक सामग्री का उपयोग एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। प्रधान मंत्री ने प्रगति के 40वें संस्करण की

अध्यक्षता की, जो सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक आईसीटी-आधारित बहु-मोडल मंच है जो केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ लाता है।

प्रमुख बिंदु:

बैठक के दौरान आठ परियोजनाओं और एक कार्यक्रम वाली नौ एजेंडा मदों की समीक्षा की गई। 14 राज्यों में इन आठ परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 59 हजार 900 करोड़ रुपये है।

झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम शामिल राज्यों में शामिल हैं।

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 'राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन' कार्यक्रम पर भी चर्चा की। राज्यों और एजेंसियों को केंद्रीकृत गति शक्ति संचार पोर्टल का उपयोग करने के लिए कहा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) आवेदनों को शीघ्रता से संसाधित किया जा सके।

प्रधान मंत्री के अनुसार, राज्य पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के आधार पर राज्य-स्तरीय गतिशक्ति मास्टर प्लान भी बना सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए राज्य-स्तरीय संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं।

5. फिनटेक स्टार्टअप महाग्राम ने इंडसइंड बैंक के साथ साझेदारी की

ग्रामीण NEO बैंक महाग्राम (Mahagram) ने देश के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटाइज़ करने और ग्रामीण भारत में अपने ग्राहकों के लिए लेन-देन की व्यापक गुंजाइश प्रदान करने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ करार किया है। महाग्राम को भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से लॉन्च किया गया था। दोनों के बीच साझेदारी का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, छाया अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करना और कैशलेस समाज के विकास में तेजी लाना है।

यह सहयोग एक कुशल, विश्वसनीय और सुरक्षित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी सुनिश्चित करेगा, जो न केवल ई-भुगतान विधियों के उपयोग को बढ़ावा देगा और प्रोत्साहित करेगा बल्कि देश भर के व्यापारियों को आसानी से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने में मदद करेगा, जिससे यह सभी के लिए अधिक सुलभ हो जाएगा।

6. मूडीज ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 8.8 प्रतिशत किया

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने उच्च मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 9.1 प्रतिशत से घटाकर 8.8 प्रतिशत कर दिया। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2022-23 के अपने अपडेट में, मूडीज ने कहा कि उच्च आवृत्ति वाले आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर तिमाही 2021 से विकास की गति इस साल पहले चार महीनों में जारी रही। हालांकि, कच्चे तेल, खाद्य और उर्वरक की कीमतों में वृद्धि का असर आने वाले महीनों में घरेलू वित्त और खर्च पर पड़ेगा। ऊर्जा और खाद्य मुद्रास्फीति को और अधिक सामान्यीकृत होने से रोकने के लिए दरों में बढ़ोतरी से मांग में सुधार की गति धीमी हो जाएगी। मजबूत ऋण वृद्धि, कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा घोषित निवेश के इरादे में बड़ी वृद्धि, और सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए उच्च बजट आवंटन से संकेत मिलता है कि निवेश चक्र मजबूत हो रहा है। 2022 और 2023 के लिए, इसने मुद्रास्फीति को क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान लगाया।

7. सोने के आयात को लेकर RBI ने जारी किए नए दिशानिर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने योग्य ज्वैलर्स को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड (IIBX) या किसी अन्य एक्सचेंज के माध्यम से सोना आयात करने की अनुमति देने के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। IFSCA और DGFT, भारत सरकार को अन्य एक्सचेंजों को मंजूरी देनी चाहिए। आरबीआई के अनुसार, आईआईबीएक्स के माध्यम से सोने के आयात के लिए अधिकृत ज्वैलर्स द्वारा सभी भुगतान आईएफएससी अधिनियम और विनियमों के अनुसार आईएफएससीए द्वारा मान्यता प्राप्त विनिमय तंत्र का उपयोग करके किया जाना चाहिए ।

प्रमुख बिंदु:

•नई सिफारिशों के अनुसार, अनुमोदित डीलर बैंक योग्य ज्वैलर्स को आईएफएससी अधिनियम के तहत प्रकाशित मौजूदा विदेश व्यापार नीति और विनियमों के अनुसार आईआईबीएक्स के माध्यम से सोने के आयात के लिए ग्यारह दिन का अग्रिम भुगतान करने की अनुमति दे सकते हैं।

•आईएफएससी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए आईएफएससीए द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एक अपरिवर्तनीय खरीद आदेश की प्रकृति में बिक्री अनुबंध या अन्य दस्तावेज की शर्तों के अनुसार, प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि आईएफएससीए द्वारा अधिकृत एक्सचेंज/एस के माध्यम से इस तरह के आयात के लिए अग्रिम

प्रेषण आईएफएससी अधिनियम और आईएफएससीए द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एक अपरिवर्तनीय खरीद आदेश की प्रकृति में बिक्री अनुबंध या अन्य दस्तावेज की शर्तों के अनुसार है।

.

•इसके अलावा, लाइसेंस प्राप्त डीलर बैंकों को सभी उचित परिश्रम करना चाहिए और गारंटी देनी चाहिए कि भेजे गए प्रेषण केवल आईएफएससीए-अनुमोदित एक्सचेंजों के माध्यम से वास्तविक आयात लेनदेन के लिए हैं।

•आरबीआई ने आगे कहा कि सोने के आयात के लिए अग्रिम प्रेषण का उपयोग किसी भी तरह से किए गए अग्रिम प्रेषण से अधिक मूल्य के सोने के आयात के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

•क्यूजे सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किए गए बिल ऑफ एंट्री (या आयात के साक्ष्य के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी/अनुमोदित कोई अन्य लागू दस्तावेज) को एडी बैंक को भेजेगा, जहां से आईआईबीएक्स के माध्यम से सोने का आयात होने पर अग्रिम भुगतान किया गया है।

8. यूनिसेफ-डब्ल्यूएचओ ने सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट जारी की

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन अस्सिसटिव टेक्नोलॉजी (GReAT) जारी की है। पेपर, जिसे यूनिसेफ के अनुसंधान कार्यालय - इनोसेंटी के संयोजन में बनाया गया था, में सभी बच्चों के लिए सहायक तकनीक तक पहुंच बढ़ाने के लिए 10 महत्वपूर्ण कार्रवाई योग्य सुझाव, साथ ही साक्ष्य-आधारित सर्वोत्तम अभ्यास उदाहरण शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

•शैक्षणिक संस्थानों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, दाताओं और चिकित्सकों के एक नेटवर्क के माध्यम से, यूनिसेफ ऑफिस ऑफ रिसर्च - इनोसेंटी विकलांग बच्चों और युवाओं की आवाज को बढ़ाने के लिए ग्लोबल रिसर्च एजेंडा और प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन की स्थापना में सबसे आगे है।

•यूनिसेफ के अनुसंधान कार्यालय - इनोसेंटी की मदद से, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट के साथ 11 फ्री-एक्सेस बैकग्राउंड पेपर्स की एक श्रृंखला बनाई।

•दुनिया भर में, 2.5 बिलियन लोगों को सहायक तकनीक की आवश्यकता है। अनुमान के मुताबिक, 2050 तक जनसंख्या 3.5 अरब लोगों तक पहुंच जाएगी।

•सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच के मामले में निम्न और मध्यम आय वाले देशों और उच्च आय वाले देशों के बीच की गहराई परेशान करने वाली है।

•कुछ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जिन व्यक्तियों को इसकी आवश्यकता है, उनके लिए सहायक तकनीक तक पहुंच 3% जितनी कम है, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह काफी अधिक है, जहां 90% तक लोगों को उनके लिए आवश्यक सहायक उपकरण और सेवाएं प्राप्त होती हैं।

•इस परिदृश्य में सहायक प्रौद्योगिकी पर डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ वैश्विक रिपोर्ट का विश्वव्यापी प्रभाव अभूतपूर्व होगा। सक्षम करने वाली सेटिंग और सहायक प्रौद्योगिकी को वैश्विक रिपोर्ट में लोगों को उनके मानवाधिकारों को समझने के लिए पूर्वापेक्षाओं के रूप में मान्यता दी गई है।

9. डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) आरोहण 4.0 शिमला में शुरू

डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी), आरोहण 4.0 के वरिष्ठ पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक हिमाचल प्रदेश के शिमला में शुरू हुई। बैठक का एजेंडा देश में वित्तीय समावेशन अभियान को और गहरा करने और भारत के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग समाधान प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा और विचार-विमर्श करना है। डाक विभाग आईपीपीबी के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और देश के कोने-कोने में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को ग्राहक-अनुकूल तरीके से लाने के लिए प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल के विजन पर काम कर रहा है।

आईपीपीबी डाक विभाग के दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क का लाभ उठाता है ताकि वरिष्ठ नागरिकों, किसानों, प्रवासी मजदूरों और महिलाओं सहित अन्य लोगों को उनके दरवाजे पर इंटरऑपरेबल बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें।

बैठक का उद्घाटन श्री आलोक शर्मा, महानिदेशक डाक सेवा ने आईपीपीबी के एमडी और सीईओ श्री जे वेंकटरामू, 23 पोस्टल सर्किलों के मुख्य पीएमजी और विभाग और आईपीपीबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। डाकघर और आईपीपीबी संचालन के बीच तालमेल को और मजबूत करने के लिए आज चर्चा हुई।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के बारे में:

बैंक की स्थापना भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत की गई है। आईपीपीबी को 1 सितंबर, 2018 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने की दृष्टि से की गई है।

10. RBI ने गैर-बैंक भारत बिल भुगतान इकाइयों के लिए निवल मूल्य की आवश्यकता को घटाया

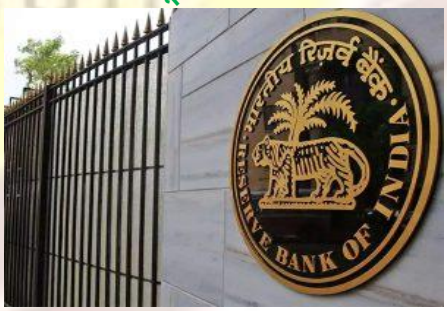

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंक संस्थाओं के लिए भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों को स्थापित करने के लिए मानदंडों को आसान बना दिया है, जिससे इस खंड में अधिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निवल मूल्य की आवश्यकता को घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्तमान में, एक गैर-बैंक बीबीपीओयू (भारत

बिल भुगतान परिचालन इकाइयों) के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए 100 करोड़ रुपये के शुद्ध मूल्य की आवश्यकता है। अप्रैल में केंद्रीय बैंक द्वारा उसी के संबंध में एक घोषणा के बाद निवल मूल्य की आवश्यकताओं में कमी आई है।

भागीदारी बढ़ाने के लिए, आरबीआई ने गैर-बैंक बीबीपीओयू की निवल संपत्ति की आवश्यकता को अन्य गैर-बैंक प्रतिभागियों के साथ संरेखित करने का निर्णय लिया था जो ग्राहक निधि (जैसे भुगतान एग्रीगेटर) को संभालते हैं और समान जोखिम प्रोफ़ाइल रखते हैं।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के बारे में:

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है और बीबीपीएस का दायरा और कवरेज उन सभी श्रेणियों के बिलर्स तक है जो आवर्ती बिल बढ़ाते हैं। बीबीपीएस के उपयोगकर्ता एक मानकीकृत बिल भुगतान अनुभव, एक केंद्रीकृत ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र और एक निर्धारित ग्राहक सुविधा शुल्क जैसे लाभों का आनंद लेते हैं।

ONE LINER

•इंडसइंड बैंक की स्थापना: 1994;

•इंडसइंड बैंक मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र;

•इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ: सुमंत कथपालिया;

•इंडसइंड बैंक टैगलाइन: वी मेक यू फील रिचर

•विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड

•संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका

QUIZ

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल- भारत ड्रोन महोत्सव-2022 का उद्घाटन किया?

a. दिल्ली b. कोलकाता
c. बेंगलुरु d. चेन्नई

a. दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल- भारत ड्रोन महोत्सव-2022 का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ड्रोन प्रदर्शनी से प्रभावित हूं. साल 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन का प्रयोग हर सेक्टर में किया जा रहा है. घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही फरवरी में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध का भी ऐलान कर दिया गया. अब केवल आरएंडडी, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए ही ड्रोन आयात की अनुमति है.

2. किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास 'टॉम्ब ऑफ सैंड' के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है?

a. प्रतिभा राय b. गीतांजलि श्री
c. उषा प्रियंवदा d. नंदिनी साहू

b. गीतांजलि श्री

लेखिका गीतांजलि श्री के अनुवादित हिंदी उपन्यास 'टॉम्ब ऑफ सैंड' को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है. यह किताब बुकर जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब बन गई है. मूल रूप से हिंदी उपन्यास 'रेत समाधि' का अंग्रेज़ी में अनुवाद डेज़ी रॉकवेल ने किया है. गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से संबंध रखती हैं. वे तीन उपन्यास एवं कई कथा संग्रह की लेखिका हैं. बता दें उनकी कृतियों का अंग्रेजी, जर्मन, सर्बियन, फ्रेंच और

कोरियन भाषाओं में अनुवाद हुआ है. गीतांजलि ने उर्दू की कई साहित्यिक कृतियों का भी अनुवाद किया है.

3. मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1 प्रतिशत से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है?

a. 7.8 प्रतिशत b. 6.8 प्रतिशत
c. 8.8 प्रतिशत d. 5.8 प्रतिशत

c. 8.8 प्रतिशत

मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने उच्चप महंगाई दर का हवाला देते हुए साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1 प्रतिशत से घटाकर 8.8 प्रतिशत कर दिया है. ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2022-23 के अपने अपडेट में मूडीज़ ने कहा कि कच्चे तेल, फूड और फर्टिलाइज़र की कीमतों में बढ़ोतरी का असर खर्च करने की क्षमता पर पड़ेगा. रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अगले वर्ष जीडीपी 5.4 फीसदी रह सकता है.

4. मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीज़ी द्वारा रिलीज़ किए गए एक अध्ययन के अनुसार, घर से काम करने के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है?

a. कराची b. दिल्ली
c. बीजिंग d. सिंगापुर

d. सिंगापुर

मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीज़ी द्वारा रिलीज़ किए गए एक अध्ययन के मुताबिक, घर से काम करने के लिए सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है. इसके बाद वॉशिंगटन, ऑस्टिन, बर्न, ज़्यूरिख, जेनेवा, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन, स्टॉकहोम और लिवरपूल का स्थान है. कीज़ी ने जर्नल ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स और विश्व बैंक के डेटा का विश्लेषण कर यह रिपोर्ट तैयार की.

5. किसने हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है?

a. जैक डोर्सी b. पराग अग्रवाल
c. धर्मेंद्र चतुर d. विनय प्रकाश

a. जैक डोर्सी

जैक डोर्सी ने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है. डोर्सी ने पिछले साल नवंबर में ट्विटर का सीईओ पद छोड़ा था और भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने उनकी जगह ली थी. उस समय ट्विटर ने कहा था कि '2022 में होने वाली शेयरधारकों की मीटिंग में अपना कार्यकाल खत्म होने तक' डोर्सी बोर्ड में बने रहेंगे.

6. भारत और किस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते (Investment Incentive Agreement) पर हस्ताक्षर किए?

a. चीन b. पाकिस्तान
c. अमेरिका d. रूस

c. अमेरिका

भारत और अमेरिका ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते (Investment Incentive Agreement) पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते पर भारत के विदेश सचिव और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (DFC) के सीईओ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे. इस समझौते से विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका के विकास वित्त संस्थान से निवेश समर्थन बढ़ाने में सहायता मिलेगी. निवेश सहायता ऋण, निवेश गारंटी, इक्विटी निवेश, पुनर्बीमा, अनुदान आदि के रूप में दी जाती है.

7. पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में 31,400 करोड़ रुपये की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की?

a. पटना b. चेन्नई

c. जयपुर d. लखनऊ

b. चेन्नई

पीएम मोदी ने हाल ही में चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपये की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की. इन परियोजनाओं में रेलवे, पेट्रोलियम, आवास और सड़कों जैसे प्रमुख बुनियादी क्षेत्र शामिल हैं. इन कार्यों से वाणिज्य और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा. इन परियोजनाओं में बैंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेसवे (Bangalore Chennai Expressway) भी शामिल है. बता दें कि, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत 116 करोड़ रुपये की लागत से 'लाइट हाउस प्रोजेक्ट-चेन्नई' के तहत निर्मित 1,152 मकानों का उद्घाटन भी किया.

8. पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है?

a. शिक्षा मंत्री b. वित्त मंत्री

c. गृह मंत्री d. मुख्यमंत्री

d. मुख्यमंत्री

पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है. राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने बताया कि राज्य विधानसभा में जल्द ही विधेयक के रूप में प्रस्ताव पेश किया जाएगा. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ वर्तमान में राज्य के 17 राज्य संचालित यूनिवर्सिटियों के पदेन कुलाधिपति हैं. बता दें कि जुलाई 2019 में राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाले हैं.